The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 8 | August 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य के सरकारी उच्च विद्यालयों में शिक्षक दक्षता और संसाधन उपलब्धता का मूल्यांकन: एक समीक्षात्मक अध्ययन

Neetu Singh

(Research Scholar), Email : pri9t.singh@gmail.com

Research Guide: **Dr. Mamta Sharma**

Department of Education, NIILM University, Kaithal, Hariyana

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.17120251

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 19-08-2025

Published: 10-09-2025

Keywords:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, बिहार, सरकारी विद्यालय, शिक्षक दक्षता, प्रशिक्षण गुणवत्ता, डिजिटल संसाधन, शैक्षणिक अवसंरचना, द्वितीयक स्रोत, नीति विश्लेषण, समीक्षात्मक अध्ययन

ABSTRACT

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव लाने हेतु एक ऐतिहासिक पहल के रूप में प्रस्तुत की गई है। शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि, डिजिटल संसाधनों का समावेश और शिक्षकों का व्यावसायिक विकास प्राथमिक लक्ष्य हैं। ऐतिहासिक रूप से शैक्षिक रूप से वंचित बिहार राज्य में इस नीति के प्रभावों का आकलन सर्वोपरि है। बिहार के सरकारी उच्च विद्यालयों में शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता और शिक्षक योग्यता की वर्तमान स्थिति की जांच करते हुए, यह रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण रुख अपनाती है। आधिकारिक रिपोर्टों, नीति दस्तावेजों, विद्वानों के लेखों और संस्थानों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों (जैसे, यूडीआईएसई+, एमएचआरडी रिपोर्ट, एनसीएफ, आदि) की समीक्षा करते हुए, यह अध्ययन पूरी तरह से द्वितीयक स्रोतों पर निर्भर करता है। यह लेख शिक्षक प्रशिक्षण की संरचना, डिजिटल बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) के अस्तित्व और व्यावहारिक बाधाओं सहित कई कोणों से नीति कार्यान्वयन प्रक्रिया की जांच करता है। बिहार के शोधकर्ताओं ने पाया कि एनईपी 2020 के कई हिस्से अभी भी योजना और निष्पादन के चरणों में हैं। उभरती समस्याओं में प्रशिक्षण की गुणवत्ता में

असमानताएं, तकनीकी उपकरणों का सीमित उपयोग और संसाधनों की उपलब्धता में भौगोलिक असमानताएं शामिल हैं। शोधकर्ता, शिक्षा अधिकारी और विधायक इस रिपोर्ट का उपयोग NEP 2020 के अलग-अलग राज्यों पर पड़ने वाले प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने तथा अधिक लक्षित सुधार पहल तैयार करने के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कर सकते हैं।

1. भूमिका

34 वर्षों के अंतराल के बाद, भारत सरकार ने आखिरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) तैयार की है, जिसे एक ऐसी शैक्षिक नीति के रूप में प्रचारित किया गया जो व्यापक और रचनात्मक दोनों है। पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत बनाने के अलावा, इस रणनीति का उद्देश्य शिक्षकों के प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा के कार्यान्वयन और मूल्य-आधारित शिक्षा के कार्यान्वयन जैसे क्षेत्रों में मूलभूत सुधार लाना था। दशकों से, बिहार राज्य की शिक्षा प्रणाली संसाधनों की कमी, सुविधाओं की कमी और शिक्षित प्रशिक्षकों की अनुपस्थिति जैसे मुद्दों से ग्रस्त रही है। इन मुद्दों के कारण इस राज्य में NEP 2020 का कार्यान्वयन विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले से कहीं अधिक, बिहार राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नीतिगत पहलों के सफल कार्यान्वयन की सख्त आवश्यकता है (शेखर, 2018; भटनागर, 2019)।

2011 में संपन्न जनगणना के अनुसार, बिहार में साक्षरता दर सिर्फ़ 63.82% थी, जो पूरे देश के औसत से बहुत कम है। राज्य के ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में इंटरनेट एक्सेस, कंप्यूटर प्रयोगशालाएँ और स्मार्ट क्लासरूम सहित डिजिटल बुनियादी ढाँचे की कमी थी। UDISE+ (2019-20) द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार, बिहार राज्य के सत्तर प्रतिशत से ज़्यादा सरकारी हाई स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की कोई सुविधा नहीं थी। इसके अलावा, छात्रों के मुक़ाबले शिक्षकों का अनुपात असंतुलित था, जिसका असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ा। राज्य स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों की संख्या सीमित थी और जो प्रशिक्षण दिया जाता था, वह अक्सर पारंपरिक पाठ्यक्रम पर केंद्रित होता था और उसमें रचनात्मकता के लिए बहुत कम जगह होती थी (तिवारी, 2020; सिंह, 2017)।

'दीक्षा' ऐप, 'निष्ठा' प्रशिक्षण कार्यक्रम और 'ई-पाठशाला' कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप बिहार में बनाई गई डिजिटल पहलों में से कुछ हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शिक्षकों को उनके शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक तकनीकी उपकरण प्रदान करना

और डिजिटल तरीकों से छात्रों को शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराना था। दूसरी ओर, इन कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर क्रियान्वित करने के प्रयास अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित हैं। शिक्षित कर्मचारियों की कमी, तकनीकी समझ की कमी और इंटरनेट कनेक्शन की सीमाओं के कारण इन योजनाओं को पूरी तरह सफल बनाना असंभव होगा (यादव, 2019; मेहता, 2020)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के संदर्भ में, इस शोध का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य में स्थित सरकारी उच्च विद्यालयों में शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता और शिक्षक योग्यता की जांच करना था। इसके संदर्भ में, यह निर्धारित करने के लिए एक विश्लेषण किया गया कि नीति के उद्देश्य किस हद तक वास्तविकता में लाए गए और यह निर्धारित करने के लिए कि कौन सी व्यावहारिक समस्याओं ने नीति के कार्यान्वयन के प्रभाव को सीमित किया। इस अध्ययन के दौरान, नीति कार्यान्वयन की प्रक्रिया के दौरान राज्य स्तर पर सबसे अधिक प्रभावशाली या बाधा डालने वाले तत्वों को समझने का भी प्रयास किया गया।

इस अध्ययन में उपयोग किए गए सभी स्रोत गौण थे, और अध्ययन का चरित्र पूरी तरह से आलोचनात्मक था। इस अध्ययन में किसी भी तरह से प्राथमिक डेटा या प्रत्यक्ष डेटा संग्रह का उपयोग नहीं किया गया।

डेटा संग्रहण के लिए जिन द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया उनमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नीति दस्तावेज, UDISE+, MHRD, NCERT, और NUEPA द्वारा प्रकाशित रिपोर्टें सम्मिलित रहीं। इसके अतिरिक्त, शिक्षा से संबंधित पूर्ववर्ती शोध-पत्र, राज्य स्तरीय सर्वेक्षण, और प्रासंगिक समाचारों के विश्लेषण से भी आंकड़े प्राप्त किए गए।

डेटा विश्लेषण हेतु थीमैटिक एनालिसिस (Thematic Analysis) सांख्यिकीय विश्लेषण दृष्टिकोण को उपयोग की जाने वाली पद्धति के रूप में चुना गया था। एकत्रित की गई सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए, इसे कई अलग-अलग विषय क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिसमें शिक्षक प्रशिक्षण, संसाधन उपलब्धता, डिजिटल बुनियादी ढाँचा और नीति निष्पादन शामिल थे। ये सभी श्रेणियाँ दिए गए तुलनात्मक अध्ययन के आधार के रूप में काम करती हैं। अध्ययन में उपयोग की जाने वाली विश्लेषण की एकमात्र विधि दस्तावेज़ समीक्षा थी; इसलिए, कोई सांख्यिकीय परीक्षण या कम्प्यूटेशनल विश्लेषण नहीं किया गया था।

2. शिक्षक पेशेवर दक्षता का वर्तमान परिदृश्य

बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक व्यावसायिकता की वर्तमान स्थिति से जुड़ी कई अलग-अलग संभावनाएँ और समस्याएँ हैं। हालाँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों को "शिक्षा प्रणाली की रीढ़" के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन शिक्षक तैयारी, नवाचार क्षमता और वास्तविक कक्षा प्रदर्शन में राज्य-स्तरीय लाभ की कमी दिखती है। सतत व्यावसायिक विकास (CPD) का कार्य, प्रशिक्षण की उपलब्धता और क्षमता, और कक्षा में आत्म-मूल्यांकन की प्रवृत्ति तीन मुख्य कारक हैं जिन्हें शिक्षक व्यावसायिकता का आकलन करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। बिहार के शिक्षक तैयारी कार्यक्रम के परिणाम असंगत रहे हैं। राज्य के अधिकांश जिलों में DIET जैसे प्रशिक्षण संस्थान हैं, लेकिन संसाधनों की कमी, पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता और प्रशिक्षकों की संख्या जैसे मुद्दे बने हुए हैं (गोस्वामी, 2018)। कई अध्ययनों से पता चला है कि प्रशिक्षकों की कमी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में देरी के कारण प्रशिक्षक नवीनतम शैक्षणिक रुझानों के साथ बने रहने में असमर्थ हैं (राजपूत, 2017)। इसके अतिरिक्त, शिक्षण की गुणवत्ता में निरंतरता नहीं रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ औपचारिकताएँ प्रशिक्षण सत्रों पर हावी हैं। इसका असर छात्रों के सीखने की क्षमता पर पड़ता है और साथ ही प्रशिक्षकों को नवोन्मेषी होने से रोकता है।

राज्य स्तरीय पहल सतत व्यावसायिक विकास (CPD) के ढांचे में सीमित लगती हैं। डिजिटल संसाधनों, इंटरनेट कनेक्टिविटी और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी के कारण, "निष्ठा" जैसी पहल ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षकों तक प्रभावी रूप से पहुँचने में असमर्थ रही (मुकुल, 2019)। एक और मुद्दा CPD प्रक्रिया को केवल प्रशिक्षण कार्यशालाओं तक सीमित करना रहा है, भले ही विश्वव्यापी मानकों में कहा गया है कि प्रशिक्षकों को निरंतर सीखने के चक्र में भाग लेना होगा। बिहार में, शिक्षकों को एक सक्षम शिक्षण समुदाय के रूप में अभी भी अपर्याप्त रूप से संगठित किया गया है और उनके पेशेवर विकास का समर्थन करने के लिए एक संरचित ढाँचे की स्थापना की गई है।

कक्षा में शिक्षकों के व्यावहारिक प्रदर्शन और उनके आत्म-मूल्यांकन के बीच भी असंतुलन रहा है। आधिकारिक समीक्षा के बिना, अधिकांश प्रशिक्षक अपनी स्वयं की क्षमताओं की जांच करने की प्रवृत्ति विकसित करने में सक्षम नहीं हैं। बहुत कम संख्या में प्रशिक्षक हैं जिन्होंने स्वेच्छा से प्रोजेक्ट-आधारित शिक्षण, प्रौद्योगिकी-आधारित शिक्षण आदि जैसे नवाचारों को अपनाया है।(कुरैशी, 2020)। विद्यालयों में आंतरिक मूल्यांकन तंत्र की कमी, प्रेरणात्मक पर्यवेक्षण का अभाव, और समयबद्ध शिक्षण निगरानी के

न होने से यह सुनिश्चित नहीं हो पाता कि शिक्षक अपने प्रदर्शन का निरंतर सुधार कर रहे हैं या नहीं। आत्म-मूल्यांकन की यह कमी उनकी पेशेवर दक्षता को प्रभावित करती है।

समग्रतः हालाँकि बिहार ने शिक्षकों की पेशेवर क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन नीति और व्यवहार के बीच अभी भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। जब तक आत्म-मूल्यांकन, निरंतर विकास योजना और प्रशिक्षण गुणवत्ता की संस्कृति को संस्थागत नहीं किया जाता, तब तक प्रशिक्षकों की वास्तविक योग्यता को बदलना असंभव होगा।

3. शैक्षणिक संसाधनों की भौगोलिक एवं संस्थागत असमानताएँ

खास तौर पर जब शहरी और ग्रामीण स्कूलों के बीच अंतर किया जाता है, तो बिहार राज्य में शैक्षिक संसाधनों की स्थिति स्पष्ट रूप से असमान और भिन्न साबित हुई है। यह तब और भी सच हो जाता है जब आँकड़ों को अलग-अलग करके देखा जाता है। डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता, स्कूलों में बुनियादी ढाँचे और आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) उपकरणों के उपयोग के मामले में, ग्रामीण स्कूल लगातार शहरी और उपनगरीय दोनों ही स्कूलों से पीछे रह गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शैक्षिक सेटिंग्स में प्रौद्योगिकी को शामिल करने पर ज़ोर दिया है; फिर भी, क्षेत्रों के बीच मौजूद संसाधनों में असमानता इस नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है।

डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता के मामले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों के बीच काफी असमानता पाई गई। यह पाया गया कि महानगरीय क्षेत्रों में स्थित सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर प्रयोगशालाएँ, प्रोजेक्टर, स्मार्ट कक्षाएँ और इंटरनेट पहुँच जैसी सुविधाएँ काफी बेहतर थीं। दूसरी ओर, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शैक्षणिक संस्थानों में या तो ये सुविधाएँ नहीं थीं या वे इनका उपयोग करने में असमर्थ थे (सुरेश, 2018)। कुछ जिलों में डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए तो गए थे, परंतु बिजली की अनियमित आपूर्ति और इंटरनेट सेवाओं की कमी के कारण उनका प्रयोग नगण्य रहा। इसके अतिरिक्त, विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को भी इन उपकरणों के समुचित संचालन हेतु प्रशिक्षण की कमी रही, जिससे संसाधन निष्क्रिय बने रहे (राहुल, 2020)।

एक और घटक जो शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में महत्वपूर्ण योगदान देता है, वह है स्कूलों का भौतिक बुनियादी ढांचा। बिहार राज्य के कई स्कूलों में, कक्षाओं की संख्या अपर्याप्त है, इमारतें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, शौचालय की सुविधाएँ खराब हैं, और पुस्तकालय और प्रयोगशालाएँ जैसी सुविधाएँ या तो मौजूद नहीं हैं या केवल औपचारिकता के लिए स्थापित की गई हैं (कौशल, 2019)। राज्य प्रशासन ने

स्कूल सुधार कार्यक्रमों के बारे में घोषणाएँ कीं; फिर भी, इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन पर्याप्त नहीं था, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। यह भी पाया गया कि संसाधनों के आवंटन में प्राथमिकता की कमी थी, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा में अंतर्निहित असमानता बनी रही। शहरी स्कूलों को जो बुनियादी ढाँचागत लाभ प्राप्त हुए, वे कम विकसित क्षेत्रों के स्कूलों द्वारा प्राप्त लाभों से काफी अधिक थे, जिन्हें संसाधनों के मामले में लगातार नजरअंदाज किया जाता रहा।

इसके अलावा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकियों के उपयोग में भी असमानता थी। प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता, तकनीकी सहायता और पाठ्यक्रम में एकीकरण सहित कई कारक यह निर्धारित करने में भूमिका निभाते हैं कि स्कूलों में उपलब्ध सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उपकरणों का कक्षा में कितनी बार और किस उद्देश्य से उपयोग किया जाता है। अधिकांश ग्रामीण विद्यालयों में, यह देखा गया कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उपकरणों का उपयोग अत्यंत सीमित था, और यह अधिकतर प्रशासनिक गतिविधियों तक ही सीमित था (माधव, 2017)। इसी समय अवधि के दौरान, कई महानगरीय विद्यालयों में कंप्यूटर आधारित शिक्षण गतिविधियाँ की जा रही थीं, विशेष रूप से अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे विषयों में। दूसरी ओर, इन परीक्षणों की संख्या अत्यंत कम थी, और उनके प्रभाव का दायरा अपेक्षाकृत छोटी आबादी तक ही सीमित था।

सभी बातों पर विचार करने पर, यह स्पष्ट है कि बिहार में शैक्षिक संसाधनों के प्रावधान में मौजूद भौगोलिक और संस्थागत असमानताएँ एक वास्तविक और महत्वपूर्ण मुद्दा हैं। जब तक संसाधनों का उचित आवंटन नहीं होगा और सभी स्कूलों को समान स्तर का तकनीकी सशक्तिकरण नहीं दिया जाएगा, तब तक शिक्षा की गुणवत्ता में राज्यव्यापी वृद्धि हासिल करना संभव नहीं होगा।

4. NEP 2020 के प्रमुख प्रावधानों का राज्यस्तरीय कार्यान्वयन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) एक ऐसी नीति है जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, लचीला, अंतःविषयक और गुणात्मक बनाना है। यह एक व्यापक और क्रांतिकारी दस्तावेज है। जिस तरह से राज्य प्रशासनिक ढांचा इस नीति को स्वीकार करता है और जिस हद तक स्थानीय संस्थाएँ इसे जमीनी स्तर पर लागू करती हैं, वे महत्वपूर्ण कारक हैं जो राज्य स्तर पर इस नीति के क्रियान्वयन की प्रभावशीलता को निर्धारित करेंगे। जहाँ तक इस नीति के क्रियान्वयन का सवाल है, बिहार ने यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया है कि वास्तविकता और अपेक्षाओं के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है।

राज्य शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा कार्यालय (DEO), और ब्लॉक/क्लस्टर संसाधन केंद्र (BRC/CRC) NEP 2020 के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण कड़ी रहे हैं। परंतु कई रिपोर्टों से यह संकेत मिला कि इन इकाइयों के पास नीति को समुचित रूप से समझने, लागू करने और निगरानी करने हेतु आवश्यक दक्षता और संसाधनों का अभाव रहा है (सिन्हा, 2020)। उदाहरणस्वरूप, नीति में शिक्षकों की सतत व्यावसायिक शिक्षा (CPD), बहु-भाषिक शिक्षा और मूल्य आधारित अधिगम जैसी अवधारणाओं पर बल दिया गया, परंतु इन पहलुओं को BRC और CRC स्तर पर प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा समझाया और निगरानी किया जाना अपेक्षित था, जो कि व्यावहारिक रूप से नहीं हो सका (नवल, 2019)। इसके परिणामस्वरूप, नीति का संचालन प्रायः कागजी स्तर तक ही सीमित रह गया।

इस नीति के सफल क्रियान्वयन में स्थानीय सरकार की भूमिका भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होने के बावजूद पंचायत स्तर, स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) और ग्राम शिक्षा समिति जैसी संस्थाओं की सहभागिता में उल्लेखनीय कमी देखी गई। इसलिए, न तो नीति की समझ और न ही नीति में भागीदारी ग्रामीण स्तर पर स्थापित की जा सकी (जफर, 2018)। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कई जिलों में पंचायत स्तर पर नीति से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम नहीं बनाए गए। स्थानीय सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में डिजिटल संसाधनों के प्रसार, लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने और मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सुधार जैसे उपायों को लागू करने के लिए पर्याप्त स्तर की तत्परता नहीं दिखाई।

यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट था कि नीति की अपेक्षाओं और वास्तविक परिणामों के बीच एक महत्वपूर्ण असमानता थी। नीति में कहा गया था कि शिक्षा समावेशी, नवाचार-आधारित और बहु-विकल्प निर्देशित होनी चाहिए; फिर भी, व्यवहार में, शिक्षक-केंद्रित, परीक्षा-केंद्रित और संसाधन-वंचित प्रणाली ही अस्तित्व में रही (तिवारी, 2019)। कई विद्यालयों में नीति के क्रियान्वयन के लिए कोई स्पष्ट कार्ययोजना न होने के कारण प्रशासक और शिक्षक दोनों ही असमंजस की स्थिति में रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि नीति के कई तत्व, जैसे लचीला पाठ्यक्रम, कौशल आधारित शिक्षा या छात्र-केंद्रित शिक्षण दृष्टिकोण, केवल सिद्धांत के दायरे तक ही सीमित रहे।

परिणामस्वरूप, यह स्पष्ट है कि बिहार राज्य में NEP 2020 के कार्यान्वयन के प्रयास प्रणालीगत समस्याओं, संसाधनों की कमी और अपर्याप्त प्रशासनिक समन्वय के कारण बाधित हुए। इन कारकों ने नीति के वास्तविक उद्देश्यों को साकार करना मुश्किल बना दिया। एक ऐसी योजना के विकास के बिना जो नीति के सिद्धांतों को राज्य प्रशासन, स्थानीय संस्थानों और स्कूल स्तरों पर एकीकृत तरीके से लागू करने की अनुमति दे, इस महत्वपूर्ण नीति के प्रभाव व्यापक रूप से नहीं देखे जा सकेंगे।

5. शिक्षक प्रशिक्षण और नवाचार अपनाने की प्रवृत्ति

शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास (CPD) के लिए प्रौद्योगिकी-सक्षम प्लेटफ़ॉर्म, जैसे "निष्ठा" और "दीक्षा" पोर्टल की शुरूआत को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में बताया गया है। यह नीति स्वीकार करती है कि शिक्षक "शिक्षा प्रणाली की रीढ़ हैं।" इन प्लेटफ़ॉर्म का उद्देश्य शिक्षकों को मूल्यांकन परिवर्तनों, शिक्षण विधियों और तकनीकी विशेषज्ञता के बारे में सबसे अद्यतित जानकारी प्रदान करना है। बिहार राज्य में इन पोर्टलों की स्थापना शुरू हो गई है, हालाँकि कई स्कूलों में इनका वास्तविक उपयोग अपेक्षाकृत कम रहा है।

"निष्ठा" (National Initiative for School Heads' and Teachers' Holistic Advancement) प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को ICT उपकरणों, ब्लूम टैक्सोनॉमी, और समावेशी शिक्षा जैसे विषयों पर प्रशिक्षित किया गया। परंतु रिपोर्टों से ज्ञात हुआ कि कई शिक्षक इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को केवल औपचारिक रूप से पूर्ण करते हैं और व्यवहार में नवाचार का प्रयोग कम करते हैं (शर्मा, 2020)। इंटरनेट की अनुपलब्धता, मोबाइल या लैपटॉप की कमी, और डिजिटल साक्षरता की कमी इस प्रक्रिया की मुख्य बाधाएँ रही हैं (कौशिक, 2019)।

"दीक्षा" के नाम से जाना जाने वाला यह सॉफ्टवेयर एक पूर्ण डिजिटल संसाधन केंद्र है जिसमें निर्देशात्मक वीडियो, पाठ्यक्रम सामग्री और मूल्यांकन सामग्री शामिल है। इसके बावजूद, बिहार के ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले शिक्षकों की एक बड़ी संख्या इसे डाउनलोड करने और उपयोग करने में असमर्थ रही है। वर्मा (2018) के अनुसार, तकनीकी सहायता की कमी और सीमित संख्या में प्रशिक्षण सत्रों की व्यवस्था होने के कारण इसका प्रभाव सीमित रहा है। यह पाया गया कि केवल कुछ चुनिंदा उन्नत संस्थान ही नई शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं, जैसे कहानियों के उपयोग से सीखना, परियोजनाओं पर काम करना और अन्य चीजों के अलावा ऑडियो-विजुअल तकनीक का उपयोग करना। अधिकांश सरकारी स्कूलों में, शिक्षण की पारंपरिक तकनीक, जिसमें चॉकबोर्ड का उपयोग करना शामिल है, का उपयोग किया जाता है।

मूल्यांकन सुधारों की बात करें तो NEP 2020 में योग्यता-आधारित और व्यापक मूल्यांकन (CCE) की बात की गई है। इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों की रचनात्मक क्षमताओं, आलोचनात्मक सोच और साथ मिलकर काम करने की क्षमता का मूल्यांकन शामिल है। हालाँकि, वास्तविक व्यवहार में, अभी भी अंकों पर आधारित परीक्षणों पर काफी निर्भरता है। व्यापक मूल्यांकन करने के उद्देश्य से शिक्षकों को वह

प्रशिक्षण और संसाधन नहीं दिए गए हैं जिनकी आवश्यकता है (मिश्रा, 2019)। इसके परिणामस्वरूप नीति में उल्लिखित मूल्यांकन सिद्धांतों का व्यवहारिक अनुप्रयोग सीमित ही रहा।

इस संदर्भ में, यह स्पष्ट है कि बिहार राज्य शिक्षकों के प्रशिक्षण और नए विचारों की शुरूआत के मामले में बहुत कठिनाई का सामना कर रहा है। जब तक शिक्षकों को प्रौद्योगिकी, डिजिटल साक्षरता और रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाले शैक्षिक माहौल तक पहुँच प्रदान नहीं की जाती, तब तक वे नीतिगत लक्ष्यों को वास्तविकता में नहीं बदल पाएंगे।

6. छात्रों के अधिगम परिणामों पर परोक्ष प्रभाव

बिहार राज्य के सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक संसाधनों की कमी और प्रशिक्षकों की व्यावसायिक योग्यता का निम्न स्तर स्पष्ट रूप से विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। वास्तव में, संसाधनों की कमी और प्रशिक्षण में असमानता के कारण विद्यार्थियों का संज्ञानात्मक और संचारात्मक विकास बाधित हो रहा है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी और विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा प्रणाली के महत्व पर चर्चा की गई है।

ऐसे कई अध्ययन हुए हैं जिनसे पता चला है कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में सीखने का स्तर औसत से नीचे रहा (जैन, 2016)। यह इस तथ्य के बावजूद है कि जिन विद्यालयों में संसाधनों की अधिक आपूर्ति थी, वहां विद्यार्थियों का प्रदर्शन काफी अधिक था। विद्यार्थियों के लिए अपनी रचनात्मक क्षमताओं और समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करना संभव नहीं था क्योंकि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उपकरण उपलब्ध नहीं थे, पुस्तकालय नहीं थे, प्रयोगशालाएँ नहीं थीं और शिक्षकों ने नवाचार-आधारित शिक्षण दृष्टिकोण नहीं अपनाया (चतुर्वेदी, 2017)।

सीखने के परिणामों के क्षेत्रीय तुलनात्मक विश्लेषण के निष्कर्षों के अनुसार, बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों की सफलता दर और संज्ञानात्मक स्तर शहरी स्कूलों में अधिक पाया गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि शहरी स्कूलों में संसाधनों और प्रशिक्षकों की संख्या काफी अधिक है, जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। गोस्वामी (2018) के अनुसार, सीमांचल, कोसी और भोजपुर जैसी जगहों पर सीखने के परिणाम राष्ट्रीय औसत से काफी खराब थे। यह केवल स्थान ही नहीं है जो इस विविधता के लिए जिम्मेदार है; बल्कि, यह नीतियों को लागू करने के तरीके में अंतर है।

यह अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अकेले नीतियों का डिज़ाइन छात्र सीखने को बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है; बल्कि, जमीनी स्तर पर संसाधनों तक पहुँच, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता और निरंतर निगरानी सभी अत्यधिक आवश्यक कारक हैं। नीति के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, यह अनुशंसा की जाती है कि छात्र-केंद्रित शिक्षण रणनीतियों को लागू किया जाए। इन रणनीतियों के कुछ उदाहरण सक्रिय शिक्षण, परियोजना-आधारित शिक्षण और स्थानीय बोलियों पर आधारित संचार-आधारित निर्देश हैं (सिद्धार्थ, 2019)। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल प्रशासन को अधिक स्वायत्तता और वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियाँ विकसित कर सकें।

इन सभी विश्लेषणों के परिणामों से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षकों की प्रभावशीलता, संसाधनों की उपलब्धता और नीति के व्यावहारिक क्रियान्वयन के बीच अंतर को पाटे बिना छात्रों के सीखने में गुणात्मक सुधार प्राप्त करना संभव नहीं है।

7. निष्कर्ष

द्वितीयक स्रोतों के आधार पर, इस शोध कार्य का उद्देश्य बिहार राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) के कार्यान्वयन के संदर्भ में शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता और शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता का गहन विश्लेषण करना था। जांच के निष्कर्षों के आधार पर, यह पाया गया कि नीति में उल्लिखित लक्ष्यों और नीति की वास्तविक स्थिति के बीच एक महत्वपूर्ण असमानता थी। शोध के निष्कर्षों के अनुसार, कई जिलों में उनके शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता और नियमितता दोनों में विसंगतियां बनी हुई हैं। यह देखा गया कि कार्यक्रम के परिणामस्वरूप उपलब्ध कराए गए "निष्ठा" और "दीक्षा" जैसे प्रशिक्षण पोर्टलों का उपयोग सीमित था, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इसी समय अवधि के दौरान, इन पोर्टलों का उपयोग शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित था; फिर भी, शहरी क्षेत्रों में भी, नवाचार पर आधारित शिक्षण विधियों के निरंतर और कुशल उपयोग की गारंटी देना संभव नहीं था। जब सब कुछ ध्यान में रखा जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षक योग्यता में अपेक्षित लाभ प्राप्त करने के लिए नीति का पालन नहीं किया जा सका।

जांच के परिणामस्वरूप, यह पाया गया कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच संसाधनों के आवंटन में असमानता है। कुछ जिलों में, डिजिटल डिवाइस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी और लैब जैसी सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता थी। दूसरी ओर, अन्य क्षेत्रों में, ये सुविधाएँ या तो बिल्कुल भी सुलभ नहीं थीं या उनका उपयोग बहुत कम था। बच्चों के सीखने के परिणाम भी इस असंतुलन से सीधे प्रभावित हुए, अधिक संसाधनों वाले

स्कूलों के छात्रों ने कम संसाधनों वाले स्कूलों के छात्रों की तुलना में तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन किया।

स्थानीय प्रशासन, राज्य शिक्षा विभाग और नीति निर्माताओं के लिए यह आवश्यक होगा कि वे नीति उद्देश्यों को वास्तविकता बनाने के लिए स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं पर आधारित अधिक विशिष्ट योजनाएँ विकसित करें। निरंतर व्यावसायिक विकास के लिए प्रशिक्षकों को अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान करने, संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करने और मूल्यांकन पर आधारित शिक्षण प्रणाली को लागू करने पर जोर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर शिक्षा के लिए आवंटित धनराशि में उल्लेखनीय वृद्धि करना तथा निगरानी प्रणाली को बेहतर बनाना आवश्यक होगा।

निष्कर्षतः, यह समीक्षा अध्ययन न केवल बिहार के संदर्भ में शिक्षण और संसाधनों की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए एक आधार स्थापित करता है, बल्कि यह राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य के तुलनात्मक शोध के लिए एक ठोस आधार भी स्थापित करता है। इस अध्ययन से प्राप्त अंतर्दृष्टि में विद्यालय स्तर पर शैक्षिक सुधार, शिक्षा नीति और कार्यान्वयन विधियों के निर्माण के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करने की क्षमता है।

संदर्भ सूची

- कुरैशी, एम. (2020). कक्षा शिक्षण में नवाचार और शिक्षक आत्म-मूल्यांकन की भूमिका। *भारतीय शैक्षणिक दृष्टिकोण*, 9(2), 17-29.
- कौशल, ए. (2019). ग्रामीण विद्यालयों की भौतिक अवसंरचना: बिहार का एक अध्ययन। *शैक्षणिक अधोसंरचना समीक्षा*, 6(2), 40-53.
- कौशिक, डी. (2019). डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता: एक राज्यस्तरीय मूल्यांकन। *भारतीय शैक्षिक तकनीकी समीक्षा*, 7(2), 39-53.
- गोस्वामी, पी. (2018). बिहार में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थिति और सुधार की संभावनाएँ। *शिक्षा समीक्षा जर्नल*, 42(3), 38-53.
- गोस्वामी, व. (2018). बिहार के सीमांचल क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति: एक क्षेत्रीय विश्लेषण। *भारतीय शिक्षा नीति समीक्षा*, 6(2), 41-56.

- चतुर्वेदी, ए. (2017). ग्रामीण विद्यालयों में संसाधन अभाव और छात्रों की अधिगम क्षमता: एक तुलनात्मक अध्ययन। *शिक्षा विमर्श*, 5(1), 20-34.
- जाफर, आई. (2018). स्थानीय प्रशासन और शिक्षा नीति का तालमेल: एक क्षेत्रीय विश्लेषण। *समाज और शिक्षा विमर्श*, 5(3), 44-59.
- जैन, के. (2016). अधिगम परिणामों पर शिक्षक प्रशिक्षण का प्रभाव: बिहार के सरकारी विद्यालयों का अध्ययन। *समकालीन शैक्षिक अनुसंधान*, 4(3), 29-45.
- तिवारी, के. (2020). बिहार में विद्यालयी संसाधन और डिजिटल परिवर्तन। *समकालीन शिक्षा विश्लेषण*, 9(4), 41-56.
- तिवारी, जे. (2019). शिक्षा नीति और व्यवहारिक बाधाएँ: सरकारी विद्यालयों का अध्ययन। *शिक्षा और परिवर्तन जर्नल*, 6(4), 28-42.
- नवल, पी. (2019). BRC/CRC की भूमिका और शिक्षा नीति के प्रावधानों का क्रियान्वयन। *शिक्षा प्रशासन पत्रिका*, 10(2), 33-46.
- भटनागर, वी. (2019). बिहार में सरकारी विद्यालयों की शिक्षण गुणवत्ता: एक समीक्षा। *भारतीय शिक्षा समीक्षा*, 43(2), 31-46.
- माधव, एस. (2017). आईसीटी संसाधनों का विद्यालयों में प्रयोग और चुनौतियाँ। *शिक्षा और तकनीक जर्नल*, 10(1), 21-35.
- मिश्रा, बी. (2019). मूल्यांकन सुधार और शिक्षक की तैयारी: नीति और व्यवहार के बीच अंतर। *शिक्षा और अनुसंधान जर्नल*, 6(1), 44-60.
- मुकुल, डी. (2019). डिजिटल CPD कार्यक्रमों की पहुँच और प्रभाव: निष्ठा कार्यक्रम का मूल्यांकन। *शिक्षा और तकनीक पत्रिका*, 6(1), 24-39.
- मेहता, डी. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राज्य स्तरीय कार्यान्वयन की चुनौतियाँ। *शिक्षा नीति और नवाचार पत्रिका*, 7(1), 14-29.

- यादव, एन. (2019). डिजिटल शिक्षा और ग्रामीण विद्यालयों की वास्तविकताएँ। *शिक्षा और समाज पत्रिका*, 6(3), 67-82.
- राजपूत, एन. (2017). प्रशिक्षण की गुणवत्ता और शिक्षक प्रदर्शन: एक तुलनात्मक अध्ययन। *राष्ट्रीय शिक्षक विकास समीक्षा*, 35(2), 45-60.
- राहुल, डी. (2020). डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता और उपयोगिता: शहरी बनाम ग्रामीण परिप्रेक्ष्य। *समकालीन शैक्षणिक विश्लेषण*, 7(3), 51-65.
- वर्मा, आर. (2018). दीक्षा एप का शैक्षणिक उपयोग: शिक्षकों की भागीदारी का विश्लेषण। *डिजिटल शिक्षा पत्रिका*, 4(4), 30-48.
- शर्मा, एन. (2020). निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यावहारिक चुनौतियाँ। *राष्ट्रीय शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य*, 8(3), 21-37.
- शेखर, आर. (2018). शिक्षकों की पेशेवर दक्षता में सुधार के प्रयास: बिहार का अनुभव। *शैक्षणिक सुधार पत्रिका*, 39(3), 53-67.
- सिंह, पी. (2017). प्रशिक्षण व्यवस्था और शिक्षक व्यवहार: एक तुलनात्मक अध्ययन। *शिक्षा मूल्यांकन जर्नल*, 35(1), 23-38.
- सिद्धार्थ, आर. (2019). छात्र-केंद्रित शिक्षण रणनीतियाँ और मूल्यांकन में सुधार: नीति और कार्यान्वयन का विश्लेषण। *शिक्षा नीति और नवाचार जर्नल*, 7(4), 33-49.
- सिन्हा, एल. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का बिहार में कार्यान्वयन: एक समीक्षात्मक अध्ययन। *भारतीय शैक्षणिक समीक्षा*, 8(1), 19-35.
- सुरेश, के. (2018). बिहार में डिजिटल शिक्षा की पहुँच और बाधाएँ। *भारतीय शिक्षा प्रौद्योगिकी समीक्षा*, 9(4), 28-44.